भारत में समावेशी शिक्षा : एक मूल्यांकन

डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव,

एसोसिएट प्रोफेसर–हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ–226017,उ.प्र.

शोध सारांश

सारांश–समावेशन शब्द का अपने आपमें कुछ खास अर्थ रखता है।समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक,दार्शनिक,सामाजिक और शैक्षिक ढ़ाँचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है । समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए ही सक्षम नहीं बनाया जा जाता है, बल्कि उन्हें सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जाता है ।इसके साथ ही लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अर्न्तक्रिया करना भी समान रूप से कितना महत्वपूर्ण है ,समावेशन के द्वारा ही जाना जा सकता है।

Keywords: *भारत,समावेशी शिक्षा,शारीरिक अक्षमता,शैक्षिक असमानता,मूल्यांकन ।*

शैक्षिक असमानता व्यक्ति, समाज,राज्य,राष्ट, एवं विश्व के लिए घातक है। शैक्षिक असमानता के कारण ,आभाव के कारण घर,परिवार,समाज, देश, विश्व सभी दुख, परेशान,पीड़ित होते हैं। मनुष्य पशु के समान हो जाता है। मानवता नष्ट होने लगती है। इसलिए जरूरी है की सभी पढ़े–लिखे ,सोंचे दृसमझे, शिक्षा ही मनुष्य को समझदार और सभ्य बनाती। इस असमानता को दूर करना मनुष्य और सरकार का परम कर्तव्य होना चाहिए। आज बहुत से राजनितिक दल लोगो को जाति धर्म में फसाकर लोगों का शोषण कर रहें हैं लोग शोषित हो रहें हैं इसका प्रमुख कारण अशिक्षा ही है। जब सभी शिक्षित हो जायेंगें तो लोग राजनीति को उतना महत्व नहीं देंगे, सम्मान कम करेंगे,पिछलग्गू नहीं रहेंगे जिस भय के कारण नेता शिक्षा में कम निवेश कर रहें हैं। आज अशिक्षा ही सारे दुखों का कारण हैं।

शिक्षा में तेजी ने तथा बेहतर करने की इच्छा ने एक चिंताजनक स्थिति भी उत्पन्न कर दी है, जहाँ विद्यार्थियों पर उपलब्धियों एवं प्रदर्शन का बड़ा दबाव हो गया है। बच्चे को मशीनी शिक्षा प्रणाली के उत्पाद के रूप में देखे जाने के कारण व्यक्तिगत विकास एवं जीवनोपयोगी कौशल विकास के महत्व को अनदेखा किया गया है। जो व्यक्ति तैयार किए जा रहे हैं, वे स्वयं विचार करने अथवा जिम्मेदारी लेने एवं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में असमर्थ हैं। शिक्षा प्रणाली द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का समावेश करते हुए बच्चे को समाज की चुनौतियों के साथ प्रभावी तरीके से निपटने योग्य बनाया जाना चाहिए। सीबीएसई ने 2012 में जीवनोपयोगी कौशल कार्यक्रम को सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंश के रूप में शामिल किया था, जिसका लक्ष्य 10 से 18 वर्ष के बीच की आयु वाले किशोर विद्यार्थी थे। सर्व शिक्षा अभियान की कार्य सूची में भी गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराने के साथ ही उच्च प्राथमिक कक्षाओं की लड़कियों को जीवनोपयोगी कौशलों का प्रशिक्षण देना भी शामिल है। देश के नागरिक के रूप में बच्चे के सर्वांगीण विकास के

लिए मूल्य आधारित शिक्षा भी आवश्यक हो गई है, जिसे स्कूल एवं कॉलेज के स्तर पर मूल्य सिखाकर, उनका पोषण एवं विकास कर प्राप्त किया जा सकता है।

वर्तमान स्थिति मध्य वर्ग की बढ़ती संख्या से भी उत्पन्न हुई है। भौतिक संसाधनों के प्रति आकर्षण एवं इनकी पूर्ति हेतु निजी स्कूलों की अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ने यह भ्रम पैदा किया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिये यह रास्ता छोटा एवं सुगम है लेकिन अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिये बहुत कुछ और भी चाहिये। कर्मठ, प्रशिक्षित, लगनशील, अध्ययनशील, संवेदनशील अध्यापक भी चाहिये जो अपने उत्तरदायित्व के प्रति समर्पित हो। शिक्षा विभाग में ऐसे समर्पित कर्मचारी भी चाहिय जो जानते हों कि अध्यापकों के साथ वे भी भारत की नई पीढ़ी को तैयार करने के पवित्र कार्य में भागीदारी कर रहे हैं। सरकारी तंत्र ने या तो इसे समझा नहीं या जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। निजी स्कूलो में बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिये जो आपाधापी प्रतिवर्ष मचती है वह शिक्षा के द्वारा जुड़ाव की नहीं, बल्कि सामाजिक अलगाव की कहानी कहती है। समाज के जिस वर्ग को अपने जीवन को ऊँचा उठाने के लिये शिक्षा ही एक मात्र उपाय दिखाई देता है, उन्हें यह पूछने का अधिकार है कि उनके बच्चों के सरकारी स्कूल निरीहता की स्थिति में क्यों रखे जा रहे हैं। जबकि सुविधा सम्पन्न वर्ग के लिये सरकारें विशेष प्रावधान करने के लिये सदैव तत्पर रहती हैं।

शिक्षा में समानता के अवसर देने का प्रावधान तो भारत के संविधान में किया गया है। समता मूलक समाज के निर्माण का मूल आधार तो शिक्षा में समानता के अवसर देना ही है। फिर सम्पूर्ण देश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र की समानांतर शिक्षा व्यवस्थाएँ क्यों है? समान स्कूल व्यवस्था को हमने भुला दिया है। अब लोगों को यही आशा है कि शिक्षा के प्रसार से जो जागृति पैदा हुई है वही आगे चलकर देश में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये समान वातावरण युक्त समान स्कूल व्यवस्था जनमत के आधार पर लागू करायेगी।

देश में शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिये बेहतर प्रयास करने होंगे। हमें समावेशी शिक्षा ही यह रास्ता दिखा सकती है। हम केवल सरकार पर ही यह जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। समाज को भी इसमें व्यापक जिम्मेदारी निभानी होगी। समाज के वंचित वर्ग के बच्चों, दिव्यांगो को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, इसे प्राथमिकता पर रखना होगा। इन्हें ही ध्यान में रखकर हमें स्कूलों, कालेजों में उनके अनुकूल संसाधनों को जुटाने का प्रयास करना होगा। जब ये बच्चे सामान्य छात्रों के साथ एक समान वातावरण में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वे अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व को भली भांति विकसित करने में सफल होंगे। आज समय की माँग है कि गरीब बच्चों, अल्पंख्यक समुदाय के बच्चों एवं दिव्यांगो को अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का व्यापक लक्ष्य समाज व सरकार मिलकर तय करे। रोजगारपरक शिक्षा तथा स्किल बेस्ड लर्निंग द्वारा ही छात्रों की योग्यता को अच्छे ढंग से तराशा जा सकता है। जिससे देश की विशाल युवा जनसंख्या राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके।

भारत में समावेशी शिक्षा को बढावा देने के लिए समावेशित विद्यालयी वातावरण के निर्माण की महती आवश्यकता है जिसमें सभी को समान रूप से शिक्षा मिले ताकि सब पढ़ें और सब बढ़ें । पाठ्यक्रम का निर्माण सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए किया जाए, जो उनकी मनरूस्थिति, रुचियों, आकांक्षाओं तथा बुद्धि क्षमता के अनुरूप हो जिससे पठन–पाठन में विशिष्ट बच्चों को असुविधा न हो । इसके आलावा शिक्षण सहायक सामग्री (रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाईल, इंटरनेट आदि तकनिकी उपकरणों) का उपयोग

करके, शिक्षण सहगामी क्रियाओं में विशिष्ट छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ ही शिक्षकों को समुचित प्रशिक्षित करके समावेशी शिक्षा को पोषित किया जा सकता है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. चतुर्वेदी शिखा, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आर0 लाल0 बुक डिपो, मेरठ, 2008
2. मित्तल एस0 आर, एकीकृत और समावेशित शिक्षा, कनिष्का प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009
3. झा एम0 एस0, समावेशी शिक्षा दृष्टिकोण और प्रक्रियाएं, एस प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005
4. शर्मा डॉ0 विमलेश, समावेशित विशिष्ट शिक्षा, शारदा पुस्तक सदन, नई दिल्ली, 2016
5. कर्ण महेन्द्र नारायण–भारत में सामाजिक परिवर्तन, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, जून 2003
6. इग्नू–सामाजीकरण और शिक्षा, ई.एस.ओ. –।।,मद्रित पाठ्यवस्तु, जून 2008
7. शर्मा प्रेमपाल–'शिक्षा में सम्पूर्ण सुधार का इंतजार', दैनिक जागरण,कानपुर 5 जून, 2017
8. सक्सेना, प्रो0 उदय वीर, भारतीय शिक्षा का इतिहास, साहित्य प्रकाशन, आगरा, 2008